भारत 2023 INDIA

जलांश

खंड 6 अंक 4 नवंबर 2023

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

संदेश

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं खुशी, समृद्धि और सफलता से परिपूर्ण, आनंदमय और खुशहाल दिवाली के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सत्य का मार्गदर्शक प्रकाश आपके कर्तव्य के मार्ग को रोशन करे।

दुर्भाग्य से, सिक्किम में एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई, जिसमें दक्षिण ल्होनक नामक ग्लेशियल झील का अचानक विस्फोट हुआ, जिसके परिणामस्वरूप तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। परिणाम गंभीर थे, तीस्ता-III बांध बह गया और तीस्ता-V बांध को काफी क्षति पहुंची। जबकि टीएल डीपी-II और टीएलडीपी-IV बांध भी प्रभावित हुए। एनडीएसए/सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों की एक समर्पित टीम ने 5-6 अक्टूबर, 2023 को क्षेत्र का दौरा किया।

इस संबंध में जल शक्ति मंत्रालय को व्यापक रिपोर्ट सौंपी गई है। इस संकट की प्रतिक्रिया में, मैंने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (हिमनद झील विस्फोट) घटनाओं की तैयारियों का आकलन करने पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। प्राथमिक एजेंडा हिमनद झील विस्फोट द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों के मद्देनजर बांधों और जल विद्युत परियोजनाओं के सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच करना था। बैठक में सीडब्ल्यूसी, एनआईएच, एनआरएससी, सी-डैक के अधिकारियों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की भागीदारी देखी गई।

एनएचपीसी, एनटीपीसी, नीपको, टीएचडीसीआईएल, कोलडैम, जेकेएसपीडीसी, जीएमआर एचईपी लिमिटेड, एसजेवीएन, नाथपा झाकरी एचपीएस और सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड सहित विभिन्न बांध-स्वामित्व वाली एजेंसियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। हम हिमनद झील विस्फोट के संपर्क में आने वाली ऐसी सभी परियोजनाओं की जोखिम क्षमता का आकलन करने और उठाए जा सकने वाले उपायों पर काम करेंगे।

आईसीओएलडी के महासचिव श्री मिशेल डी वीवो, आईएनसीओएलडी और सीबीआईपी के अन्य अधिकारियों के साथ इस महीने के दौरान मुझसे मिले। "लोगों, जल, पर्यावरण और विकास के लिए बांध" विषय पर आईसीओएलडी 2024 कार्यक्रम की 92वीं आई सीओएलडी वार्षिक बैठक और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी की मेजबानी के संबंध में चर्चा की गई। यह भव्य आयोजन 18 से 24 अक्टूबर, 2024 तक आईटीपीओ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित करने की योजना है। इसके अलावा, डेनमार्क के राजदूत श्री फ्रेडी स्वेन, रॉयल डेनिश दूतावास के काउंसलर श्री कैस्पर नॉनबो श्रोडर मायलेनेल के साथ 20 अक्टूबर, 2023 को मुझसे मिलने के लिए सीडब्ल्यूसी आए। सीडब्ल्यूसी में स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के संबंध में चर्चा की गई।

पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, केंद्रीय जल आयोग ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए 'एक तारीख-एक घंटा' अभियान के तहत कई कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अभियान ने स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण बनाए रखने के सामूहिक प्रयास में व्यापक भागीदारी को प्रेरित करने का प्रयास किया।

कुल मिलाकर सीडब्ल्यूसी द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों के संदर्भ में यह एक संतोषजनक महीना था।

विषयसूची

एनडीएसए और डीआरआईपी

- 100 से अधिक निर्दिष्ट बांधों वाले राज्यों और 100 से कम निर्दिष्ट बांधों वाले राज्यों के साथ बैठकें
- बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना की दूसरी तकनीकी समिति की बैठक

परियोजना के संबंध में बैठक

- पोलावरम सिंचाई परियोजना
- मुल्लापेरियार बांध
- सुबनसिरी निचली परियोजना
- ऊपरी इंद्रावती पंप भंडारण परियोजना
- मेडीगड्डा (लक्ष्मी) बैराज, तेलंगाना
- पोंग, पोंडोह, पारबती-III और मलाणा-II बांध
- करम बांध मध्यम सिंचाई परियोजना, धार जिला, मध्य प्रदेश

प्रशिक्षण / कार्यशाला

- सात (7) नदी घाटियों में तलछट दर और तलछट परिवहन के आकलन के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग
- डीआरआईपी चरण II के तहत पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) कार्यशाला
- रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस का अनुप्रयोग
- आरआईबीएएसआईएम का उपयोग करके नदी बेसिन मॉडलिंग

दौरा/निरीक्षण

- सीपीएमयू टीम ने आईसीईडी, आईआईटी रूड़की का दौरा किया
- तीस्ता बेसिन बांध, सिक्किम में परियोजनाओं पर प्रभाव पर साइट का दौरा

अन्य गतिविधियाँ

- बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की समिति, (आई एन कोल्ड), भारत
- फरक्का में गंगा/गंगा जल बंटवारे पर 1996 की भारत-बांग्लादेश संधि की "आंतरिक समीक्षा" के लिए गठित समिति की दूसरी बैठक
- ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (हिमनद झील विस्फोट) घटनाओं की तैयारी

एनडीएसए और डीआरआईपी

100 से अधिक निर्दिष्ट बांधों वाले राज्यों और 100 से कम निर्दिष्ट बांधों वाले राज्यों के साथ बैठकें

श्री संजय कुमार सिब्बल, अध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) और सदस्य (डी एंड आर) की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में 30 अक्टूबर, 2023 को 100 से अधिक निर्दिष्ट बांध वाले राज्यों और 31 अक्टूबर, 2023 को 100 से कम निर्दिष्ट बांध वाले राज्यों से हाइब्रिड मोड का उपयोग कर चर्चा हुई।

एजेंडा में विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें बड़े (विशिष्ट) बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर-2023 में निर्दिष्ट बांधों की सूची को अद्यतन करना, 2023-24 के लिए प्री-मानसून निरीक्षणों की समीक्षा और श्रेणी-I और II बांधों की राज्य-वार स्थिति के साथ-साथ पुनर्वास के लिए की गई कार्रवाई शामिल है।

बैठक में मानसून के बाद के निरीक्षणों की तैयारी, बांध लॉग बुक के रखरखाव, जल-मौसम विज्ञान और भूकंप विज्ञान के लिए उपकरणों की स्थिति और जोखिम मूल्यांकन अध्ययनों के अनुपालन जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, निर्माणाधीन निर्दिष्ट बांधों के लिए डायवर्जन व्यवस्था और प्रस्तावित जलाशय भरने के तरीकों, ओ एंड एम मैनुअल का पालन, राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (एसडीएसओ) में स्टाफिंग, बांध सुरक्षा के लिए बजट निर्माण और बांध सुरक्षा इकाइयों की स्थापना पर भी विचार किया गया। बैठक में व्यापक बांध सुरक्षा अध्ययन, जल विज्ञान, बांध नींव, संरचनात्मक इंजीनियरिंग और बांधों के निचले प्रवाह में भूमि उपयोग से संबंधित तकनीकी दस्तावेज की समीक्षा शामिल थी।

अंत में, इसमें वार्षिक रिपोर्ट की स्थिति, आपातकालीन कार्य योजनाओं और अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार राज्य बांध सुरक्षा समितियों (एससीडीएस) की अनिवार्य अर्ध-वार्षिक बैठकों के अनुपालन को शामिल किया गया।

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना तकनीकी समिति की दूसरी बैठक

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) सीडब्ल्यूसी ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण II के लिए तकनीकी समिति (टीसी) की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की, जो 26.10.2023 को विश्व बैंक, नई दिल्ली के कार्यालय में आयोजित की गई थी। बैठक में केंद्रीय जल आयोग, विश्व बैंक, एआईआईबी, डीआरआईपी कार्यान्वयन एजेंसियों के सदस्यों/प्रतिनिधियों और अन्य केंद्रीय संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। डीआरआईपी चरण II की सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों की प्रगति, विभिन्न घटकों के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति, तकनीकी, वित्तीय और खरीद पहलू सहित परियोजना

कार्यान्वयन में समस्याएँ और चुनौतियां, धर्म पर प्रगति आदि पर प्रकाश डाला गया।

परियोजना के संबंध में बैठक

पोलावरम सिंचाई परियोजना

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डीएंडआर) ने पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के लिए आंतरिक बैठक में भाग लिया, जो 18.10.2023 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में भौतिक मोड में आयोजित की गई थी। बैठक में श्री अनिल जैन, सीई, डिज़ाइन (एनडब्ल्यू एंड एस) यूनिट और सीडब्ल्यूसी के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। श्रीमती देबाश्री मुखर्जी, सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर ने बैठक की अध्यक्षता की, और इसमें माननीय मंत्री (जल शक्ति) के सलाहकार और के.ज.आ., पीपीए, सीएसएमआरएस, एम/एस वाप्कोस और डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में चर्चा किए गए कुछ कार्य बिंदुओं में एक विशेषज्ञ एजेंसी की नियुक्ति और अंतरिम उपाय के रूप में व्यक्तिगत विशेषज्ञों की नियुक्ति, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कोफ़र बांधों और डी दीवार में सीपेज, और खराब उपचार का मुद्दा, एनएचपीसी द्वारा पीआईपी के संतुलन कार्यान्वयन की संभावना, परियोजना के डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एसओपी, कार्यकारी मौसम 2023-24 आदि के लिए कार्य योजना शामिल हैं।

मुल्लापेरियार बांध

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी द्वारा 25.10.2023 को अध्यक्ष के कक्ष में मुल्लापेरियार बांध से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में ली गई बैठक में भाग लिया।

सुबनसिरी निचली परियोजना

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 27.10.2023 को श्रमशक्ति भवन में 27.10.2023 को सुबनसिरी निचली परियोजना के संबंध में एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत घटना रिपोर्ट के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सचिव (विद्युत) द्वारा ली गई बैठक में भाग लिया।

बैठक में 27.10.2023 को हुए बड़े भूस्खलन की घटना रिपोर्ट पर चर्चा की गई और नियोजित कार्यों पर इसके प्रभाव का भी मूल्यांकन किया गया।

ऊपरी इंद्रावती पंप भंडारण परियोजना

श्री विशाल कुमार देव, प्रधान सचिव, ओडिशा सरकार और अध्यक्ष ओएचपीसी ने 20.10.2023 को केंद्रीय जल आयोग का दौरा किया और श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और पदेन सचिव, भारत सरकार से उनके कार्यालय में मुलाकात की।

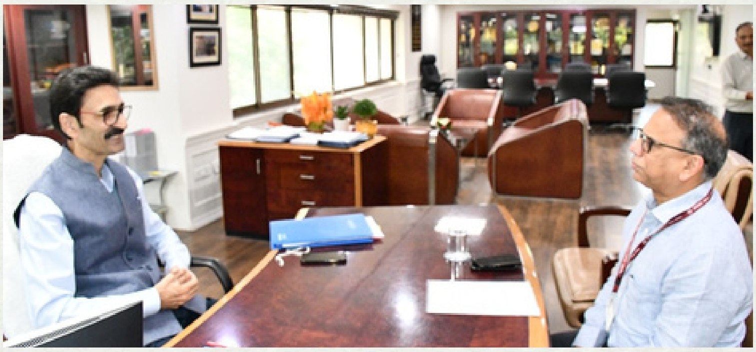

600 मेगावाट की अपर इंद्रावती पंप भंडारण परियोजना, 500 मेगावाट की बालीमेला और 320 मेगावाट की अपर कोलाब पंप भंडारण परियोजना के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने बताया कि ऊपरी इंद्रावती पीएसपी डीपीआर चरण में है और परियोजना अधिकारियों द्वारा कुछ भूवैज्ञानिक जांच की जानी है। इसके अलावा, अपर कोलाब और बालिमेला पंप स्टोरेज परियोजनाएं पीएफआर चरण में हैं। परियोजना अधिकारियों ने अभी तक इन पीएफआर की जांच के लिए प्रासंगिक डिज़ाइन विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने आश्वासन दिया कि एक बार परियोजना अधिकारियों द्वारा अपेक्षित विवरण/रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद, सीडब्ल्यूसी इन डीपीआर/पीएफआर का विशेष रूप से मूल्यांकन करेगा। प्रधान सचिव, ओडिशा सरकार ने प्रतिक्रिया की सराहना की और आश्वासन दिया कि अपेक्षित जानकारी शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।

प्रशिक्षण / कार्यशाला

सात (7) नदी घाटियों में तलछट दर और तलछट परिवहन के आकलन के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग

सात नदी घाटियों में तलछट दर और तलछट परिवहन के आकलन के लिए "भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग" विषय पर 17 अक्टूबर 2023 को तीसरी मंजिल के सम्मेलन कक्ष, सेवा भवन, नई दिल्ली में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली द्वारा किया गया। कार्यशाला में सात नदी घाटियों में तलछट उत्पादन और तलछट परिवहन के आकलन के परिणाम और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई।

डीआरआईपी चरण II के तहत पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) कार्यशाला

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण II के लिए पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) कार्यशाला में भाग लिया, जो 27.10.2023 को आयोजित की गई थी। श्री विजय सरन, सीई, डीएसओ, सीडब्ल्यूसी और डीआरआईपी चरण II के परियोजना निदेशक के साथ-साथ सीपीएमयू अधिकारियों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया, जो विश्व बैंक, नई दिल्ली के कार्यालय में आयोजित की गई थी। कार्यशाला में सीपीएमयू, विश्व बैंक, आईए के एसपीएमयू के साथ-साथ उनके ईएंडएस नोडल अधिकारी/ईएंडएस विशेषज्ञ भी शामिल हुए। विश्व बैंक के अधिकारियों द्वारा ईएंडएस पर प्रस्तुति दी गई जिसमें डीआरआईपी योजना के पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। केडब्ल्यूआरडी, केएसईबी, गुजरात आदि के ईएंडएस नोडल अधिकारियों ने भी डीआरआईपी II के तहत बांधों के पुनर्वास के लिए ईएंडएस अनुपालन की प्रक्रिया के दौरान अपने अनुभव और मुद्दों के संबंध में संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस का अनुप्रयोग

अध्यक्ष (सीडब्ल्यूसी) और भारत सरकार के पदेन सचिव, श्री कुशविंदर वोहरा के निर्देशों के अनुसरण में, विशेष क्षेत्रों जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर और अन्य की प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, राष्ट्रीय जल अकादमी, केंद्रीय जल आयोग द्वारा संचालित जल संसाधन विभाग, अरुणाचल प्रदेश के अधिकारियों के लिए "रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के अनुप्रयोग" पर 5 दिवसीय अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आज ईटानगर में शुरू हुआ।

यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग के विशिष्ट अनुरोध के जवाब में सोच-समझकर तैयार किया गया है।

अपने उद्घाटन भाषण के दौरान, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय जल अकादमी ने इन क्षेत्रों की चुनौतीपूर्ण स्थलाकृति और भारी वर्षा पैटर्न को देखते हुए, इन क्षेत्रों में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की योजना और तैयारी में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से शामिल होने और प्रशिक्षण कार्यक्रम का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने नए ज्ञान को प्रभावी

ढंग से लागू करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। मुख्य अभियंता ने आगे बताया कि राष्ट्रीय जल अकादमी पूरे वर्ष विभिन्न प्रशिक्षण सत्र आयोजित करती है, और प्रतिभागियों को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में रिमोट सेंसिंग के बुनियादी सिद्धांतों सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें जीआईएस, क्यूजीआईएस का उपयोग करके व्यावहारिक अभ्यास, विभिन्न प्रकार के स्थानिक डेटा के साथ काम करना, ओपन-एक्सेस उपग्रह इमेजरी और डेटा स्रोतों का उपयोग, भू-संदर्भ, डिजिटलीकरण, बुनियादी स्थानिक विश्लेषण, मानचित्र निर्माण, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग, स्वाट मॉडलिंग, वाटरशेड गुण, और विभिन्न व्यावहारिक सत्र शामिल है।

आरआईबीएएसआईएम का उपयोग करके नदी बेसिन मॉडलिंग

राष्ट्रीय जल अकादमी, केंद्रीय जल आयोग, पुणे भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी, चरण 2, के सहयोग से 9 से 19 अक्टूबर, 2023 के दौरान RIBASIM का उपयोग करके 'रिवर बेसिन मॉडलिंग' पर एक इंटरैक्टिव और व्यावहारिक प्रशिक्षण का आयोजन कर रहा है जिसे एक जर्मन विकास एजेंसी जीआईजेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

IEWP कार्रवाई चरण 2 के चार विषयगत क्षेत्रों में से एक नदी बेसिन प्रबंधन (आरबीएम) है। तापी और रामगंगा बेसिन हेतु आरबीएम योजनाओं के विकास की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए, RIBASIM मॉडल का उपयोग किया गया यह देखने के लिए कि पानी की मांग, उपयोग और आवंटन का अनुकरण करने और यह अनुमान लगाने के लिए कि पानी की उपलब्धता पर भविष्य के सामाजिक-आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के परिदृश्यों में परियोजनाएं कैसे कार्य करेंगी।

विभिन्न सरकारी एजेंसियों से भारतीय अधिकारियों की प्रासंगिक क्षमता विकास को प्राप्त करने के लिए एनडब्ल्यूए, सीडब्ल्यूसी,

पुणे परिसर में RIBASIM मॉडल पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसार विभाग, गुजरात सरकार के 13 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।

डॉ. कीस बॉन्स, नदी बेसिन प्रबंधन और योजना विशेषज्ञ डेल्टारेस, नीदरलैंड प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान संसाधन व्यक्ति/अतिथि संकाय के रूप में कार्य करेंगे।

दौरा/निरीक्षण

सीपीएमयू टीम का आईसीईडी, आईआईटी रूड़की दौरा

श्री एस.एस. बख्शी, निदेशक, डीएसआर निदेशालय और श्री भिसे योगेश नानासाहेब, उप निदेशक, डीएसआर निदेशालय ने ड्रिप चरण-द्वितीय और चरण-तृतीय.के तहत अंतर्राष्ट्रीय बांध उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी), आईआईटी रूड़की के विकास के संबंध में आईसीईडी टीम के साथ प्रगति समीक्षा बैठक की।

आईसीईडी की ओर से प्रोफेसर एन.के.गोयल, प्रमुख, आईसीईडी, प्रोफेसर एम.एल.शर्मा, थीम समन्वयक, भूकंपीय खतरा मानचित्रण और विश्लेषण उपस्थित थे। सीपीएमयू द्वारा पहले आईसीईडी के साथ साझा किए गए एजेंडे के अनुसार चर्चा की गई। श्री एस.एस.बख्शी,निदेशक, डीएसआर निदेशालय ने बांध सुरक्षा एवं पुनर्वास पर एमटेक पाठ्यक्रम के छात्रों को 'बांध सुरक्षा अधिनियम, इसके अवलोकन, प्रावधानों और संगठनों के कर्तव्यों' पर विशेषज्ञ व्याख्यान दिया। इसके अलावा, सीपीएमयू टीम ने आईसीईडी के नवीकरण स्थल का भी दौरा किया; निर्माणाधीन वेस्टर्न एकेडमिक ब्लॉक-बी साइट का दौरा किया, जिसमें 4-6 मंजिल पर आईसीईडी की स्थायी स्थापना होगी; और संस्थान के बोटक्लब साइट का दौरा किया, जहां संस्थान द्वारा आईसीईडी को जलाशय अवसादन और गाद नियंत्रण विषय के तहत आवश्यकतानुसार भौतिक मॉडलिंग प्रयोगशाला का विकास करने के लिए 800 वर्ग मीटर जगह आवंटित की गई है।

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) ल्होनक झील, उत्तरी सिक्किम के कारण तीस्ता बेसिन बांध, सिक्किम में परियोजनाओं पर प्रभाव पर साइट का दौरा

सिक्किम में दक्षिण लोनाक ग्लेशियल झील में अचानक विस्फोट के कारण 03-04 अक्टूबर 2023 की रात को तीस्ता नदी में बाढ़ (जीएलओएफ) आ गई, जिससे तीस्ता-III बांध बह गया और तीस्ता-V बांध को भारी क्षति हुई। टीएलडीपी-II बांध और टीएलडीपी-IV बांध भी प्रभावित हुए हैं लेकिन किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है।
सदस्य (आपदा एवं लचीलापन) श्री अनिल जैन के नेतृत्व में एनडीएसए/सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों की एक टीम ने 05-06 अक्टूबर 2023 को तीस्ता बेसिन का दौरा किया और रिपोर्ट जल शक्ति मंत्री को सौंप दी गई है।

जीएलओएफ के बाद तीस्ता-III बांध

मेडीगड्डा (लक्ष्मी) बैराज, तेलंगाना

21/10/2023 की रात को मेडीगड्डा बैराज के घाट की बंदोबस्ती के कारण अचानक 2.7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बैराज का निर्माण 2019 में पूरा हुआ। श्री अनिल जैन, सदस्य (आपदा एवं तन्यकता) के नेतृत्व में एनडीएसए/सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों की एक टीम ने 23-26 अक्टूबर 2023 के दौरान साइट का दौरा किया और रिपोर्ट तैयार की गई और डॉ. रजत कुमार, विशेष मुख्य सचिव, सिंचाई और सीएडी, तेलंगाना को भेज दी गई।

(मेडिगाड्डा बैराज के घाट में आई दरार)

पोंग, पोंडोह, पारबती-III और मलाणा-II बांध

श्री गोवर्धन प्रसाद, निदेशक, जल विज्ञान (निदेशालय) ने पोंग का विस्तृत निरीक्षण करने के लिए सीडब्ल्यूसी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आर.के. गुप्ता की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में पोंग, पोंडोह, पारबती-III और मलाणा-II बांधों का दौरा किया। , पंडोह और पार्बती बांध में अचानक पानी छोड़े जाने के संबंध में और मलाणा-द्वितीय बांध में 16 से 21 अक्टूबर, 2023 के दौरान ओवर टॉपिंग की घटना के संबंध में भी।

करम बांध मध्यम सिंचाई परियोजना, धार जिला, मध्य प्रदेश

जल संसाधन के अधिकारियों के साथ केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अधिकारी भी शामिल हुए विभाग (डब्ल्यूआरडी), मध्य प्रदेश सरकार ने 14.10.2023 को करम बांध मध्यम सिंचाई परियोजना, धार जिला, मध्य प्रदेश परियोजना स्थल का दौरा किया। सीडब्ल्यूसी टीम का नेतृत्व श्री अनिल जैन, मुख्य अभियंता, डिजाइन (एनडब्ल्यू एंड एस), सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली ने किया।

डब्ल्यूआरडी, एमपी द्वारा जारी डिजाइन और ड्राइंग की जांच के लिए सीडब्ल्यूसी को समीक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके लिए 11.09.2023 को सीडब्ल्यूसी और डब्ल्यूआरडी, एमपी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दौरे पर आई टीम ने आंशिक रूप से पूर्ण/टूटे हुए करम बांध की वर्तमान स्थिति देखी। सीडब्ल्यूसी टीम ने अगस्त, 2022 में बांध टूटने की घटना के बाद की गई जांच का संज्ञान लिया।

निर्माण सामग्री की उपलब्धता और निर्माण योजना एवं प्रबंधन के मुद्दों पर चर्चा हुई। बांध स्थल के विस्तृत मूल्यांकन के बाद, सीडब्ल्यूसी ने निर्माण कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक कदमों/कार्रवाई की सिफारिश की।

सीडब्ल्यूसी की अन्य गतिविधियाँ

बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की समिति, (आईएनसीओएलडी), भारत

आईसीओएलडी के महासचिव श्री मिशेल डी वीवो और आईएनसीओएलडी और सीबीआईपी के अन्य अधिकारियों ने 27.10.2023 को केंद्रीय जल आयोग का दौरा किया और केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा से उनके कार्यालय में मुलाकात की।

बड़े बांध अंतर्राष्ट्रीय आयोग भारत की समिति, (INCOLD), 18 से 24 अक्टूबर 2024 तक आईटीपीओ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में "लोगों के लिए बांध, जल, पर्यावरण और विकास" विषय पर 92वीं आईसीओएलडी वार्षिक बैठक और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी सहित प्रतिष्ठित ICOLD 2024 कार्यक्रम की मेजबानी कर रही है।

बातचीत के दौरान, श्री मिशेल डी वीवो ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और इसकी प्रगति और आयोजनों की व्यवस्था पर चर्चा की गई। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष से आईसीओएलडी 2024

कार्यक्रम के लिए सीडब्ल्यूसी और डीआरआईपी से संरक्षण और लोगो समर्थन बढ़ाने और इस उद्देश्य के लिए गठित तकनीकी समिति को सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया। अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में सभी प्रकार के समर्थन का आश्वासन दिया।

फरक्का में गंगा/गंगा जल बंटवारे पर 1996 की भारत-बांग्लादेश संधि की "आंतरिक समीक्षा" के लिए गठित समिति की दूसरी बैठक

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने "फरक्का में गंगा/गंगा जल बंटवारे पर 1996 की भारत-बांग्लादेश संधि की आंतरिक समीक्षा" के लिए दूसरी समिति की अध्यक्षता की, जो 30.10.2023 सीडब्ल्यूसी समिति कक्ष, द्वितीय तल, सेवा भवन में आयोजित की गई थी। बैठक में श्री मनोज तिवारी, सीई, एचएसओ, श्री एन.एन.राय, निदेशक, जलविद्युत (एनई) और सीडब्ल्यूसी, फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी), आई एंड डब्ल्यूडी, पश्चिम बंगाल सरकार, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर और डब्ल्यूआरडी, बिहार सरकार के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य अभियंता (एचएसओ), सीडब्ल्यूसी ने गंगा जल संधि, समिति के टीओआर, फरक्का बैराज परियोजना और बिहार सरकार से प्राप्त इनपुट के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। सदस्य (डी एंड आर), सीडब्ल्यूसी और समिति के अध्यक्ष ने सदस्यों को वर्तमान संधि के मुद्दों और राज्यों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करने पर जोर दिया। विस्तृत चर्चा के बाद समिति ने महत्वपूर्ण निर्णय लिये।

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (हिमनद झील विस्फोट) घटनाओं की तैयारी

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) घटनाओं की तैयारियों के संबंध में 19 अक्टूबर, 2023 को एक बैठक की। बैठक में सीडब्ल्यूसी, एनआईएच, एनआरएससी, सी-डैक, हिमाचल प्रदेश एसडीएसओ, उत्तराखंड एसडीएसओ, सिक्किम एसडीएसओ, सिक्किम एसडीएमए और विभिन्न बांध स्वामित्व एजेंसियों जैसे एनएचपीसी, एनटीपीसी, एनईईपीसीओ, टीएचडीसीआईएल, कोलडैम, जेकेएसपीडीसी, जीएमआर एचईपीएलटीडी, एसजेवीएन नाथपा झाकरी एचपीएस, सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड आदि के अधिकारियों ने भाग लिया। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष ने बताया कि बैठक का मुख्य एजेंडा जीएलओएफ के संभावित खतरे से बांधों और जल विद्युत परियोजनाओं के सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बांध मालिक एजेंसियों को जीएलओएफ को ध्यान में रखते हुए डिजाइन बाढ़ की समीक्षा करनी चाहिए ताकि स्पिलवे की पर्याप्तता सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, जीएलओएफ से

जुड़े जोखिम को कम करने के लिए इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। सभी परियोजना प्राधिकरण/एसडीएमए इस बात पर सहमत हुए कि वे जीएलओएफ के सामने आने वाली परियोजनाओं और इन्हें जीएलओएफ पर विचार करते हुए विधिवत डिजाइन किया गया है या नहीं के बारे में 15 दिनों के भीतर जानकारी प्रदान करेंगे तथा प्रत्येक मामले में स्थापित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थिति के बारे में भी सूचित करेंगे।

बाढ़ प्रवण क्षेत्र के वैज्ञानिक मूल्यांकन पर प्रस्तुति

लैंडसैट और सेंटिनेलोन गूगल अर्थ इंजन एप्लिकेशन इंटरफ़ेस और जीआईएस की उपग्रह छवियों का विश्लेषण करके चित्रित भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के समग्र विस्तार पर अध्ययन की समीक्षा करने के लिए 17.10.2023 को अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी।

आईसीआईडी के आयोजन के संबंध में संचालन समिति की दूसरी बैठक

25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और आईसीआईडी की 74वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक (आईईसी) की तैयारी की प्रगति की समीक्षा के लिए संचालन समिति की दूसरी बैठक 13 अक्टूबर, 2023 को सचिव, DoWR, RD&GR की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, वीजा से संबंधित मामलों, एमएचए सुरक्षा मंजूरी की स्थिति, कार्यक्रम के उद्घाटन की स्थिति, सम्मेलन के लिए धन जारी करने की स्थिति, मीडिया पार्टनर की सेवाओं की भागीदारी, सांस्कृतिक संध्या की स्थिति आदि पर चर्चा की गई।.

डेनमार्क के राजदूत के साथ बातचीत

डेनमार्क के राजदूत श्री फ्रेडी स्वेन ने रॉयल डेनिश दूतावास के काउंसलर श्री कैस्पर नॉनबो श्रोडर मेलेनेल के साथ 20.10.2023 को केंद्रीय जल आयोग का दौरा किया और श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और पदेन सचिव, भारत सरकार से उनके कार्यालय में मुलाकात की।

बातचीत के दौरान, स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की स्थिति पर चर्चा की गई। अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने बताया कि इस संबंध में विचारों से डेनमार्क पक्ष को 07 जून, 2023 को अवगत कराया गया था। हमारी दो मुख्य चिंताएं हैं, पहली परियोजना में शामिल सीडब्ल्यूसी अधिकारियों की क्षमता निर्माण। दूसरी, अध्ययन के दौरान विकसित मॉडल डेनमार्क पक्ष का प्रतिलिपि अधिकार नहीं होना चाहिए और भारत और डेनमार्क को आगे के

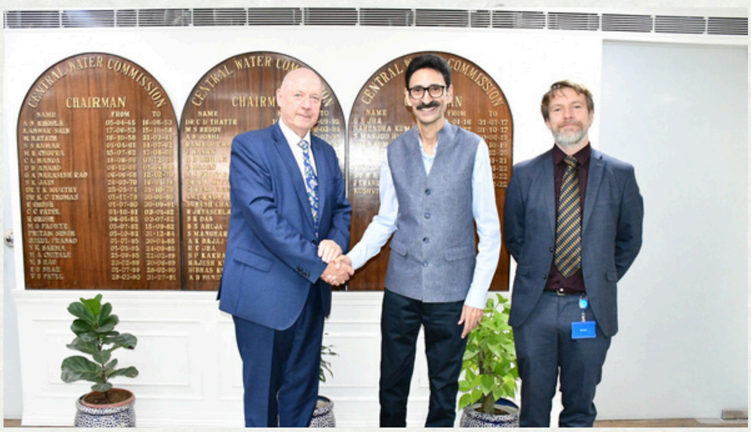

अध्ययन के लिए इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।

डेनमार्क के राजदूत एवं श्री कैस्पर ने सुझावों पर सहमति व्यक्त की।

आईसीआईडी की तैयारी की प्रगति की समीक्षा के लिए आईएनसीआईडी की आयोजन समिति की छठी बैठक

25वीं कांग्रेस और आईसीआईडी की 74वीं आईईसी की आयोजन समिति की छठी बैठक 23 अक्टूबर, 2023 को सीडब्ल्यूसी/आईएनसीआईडी के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।

समिति ने मंजूरी, पंजीकरण, वीज़ा, निमंत्रण और प्रायोजन, तकनीकी सत्र, फंड रिलीज की स्थिति, उद्घाटन की स्थिति, आईसीआईडी के अनुसार तीसरी घोषणा की रिलीज की स्थिति और सांस्कृतिक शाम के लिए तैयारियों की स्थिति सहित कार्यक्रम के आयोजन की प्रगति पर चर्चा की।

25वीं कांग्रेस और आईसीआईडी की 74वीं आईईसी की आयोजन समिति की छठी बैठक 23 अक्टूबर, 2023 को सीडब्ल्यूसी/आईएनसीआईडी के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।

समिति ने मंजूरी, पंजीकरण, वीज़ा, निमंत्रण और प्रायोजन, तकनीकी सत्र, फंड रिलीज की स्थिति, उद्घाटन की स्थिति, आईसीआईडी के अनुसार तीसरी घोषणा की रिलीज की स्थिति और सांस्कृतिक शाम के लिए तैयारियों की स्थिति सहित कार्यक्रम के आयोजन की प्रगति पर चर्चा की।

जलाशय निगरानी

सीडब्ल्यूसी साप्ताहिक आधार पर देश के 150 जलाशयों की लाइव स्टोरेज स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 20 जलाशय पनबिजली परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 35.299 बीसीएम है। इन 150 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 178.784 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित भंडारण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 69.35% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 26.10.2023 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 127.591 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 71% है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण 159.375 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहण 138.843 बीसीएम था। इस प्रकार, 6.10.2023 बुलेटिन के अनुसार 150 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सजीव संग्रहण का 80% और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 92% है।

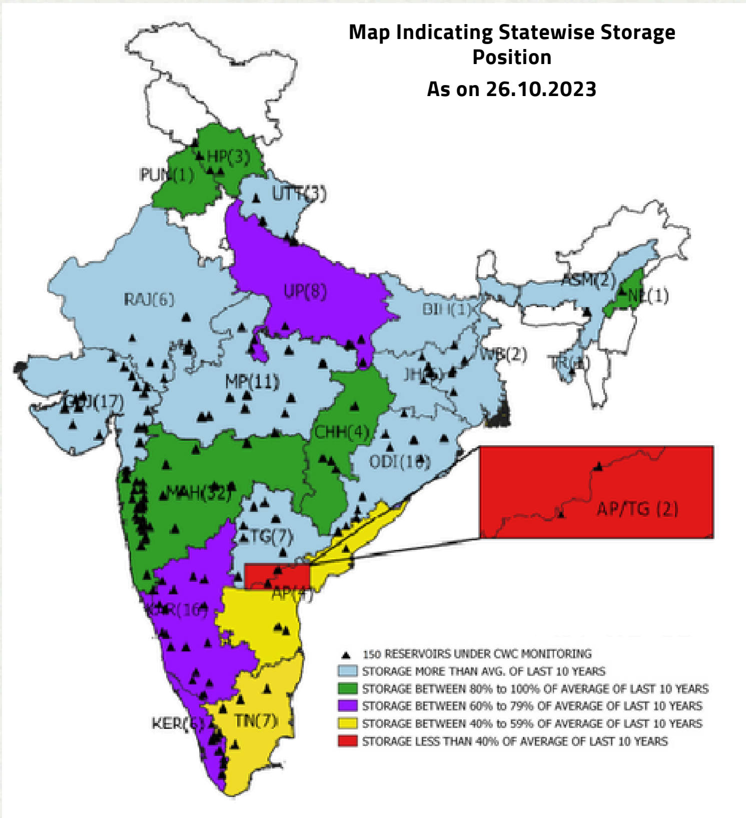

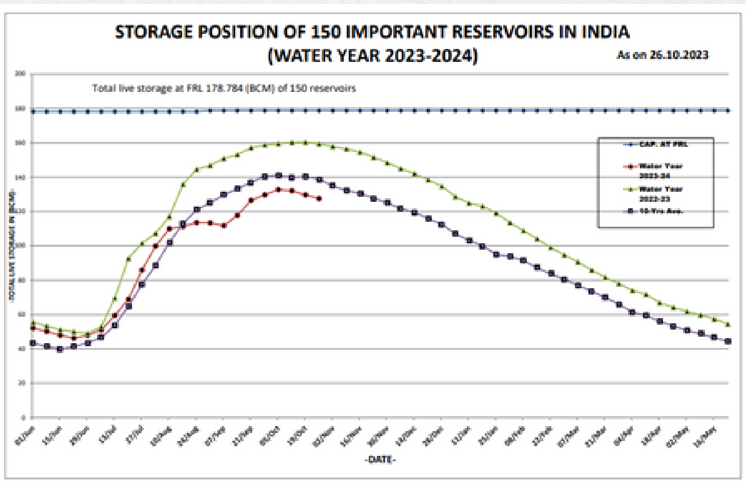

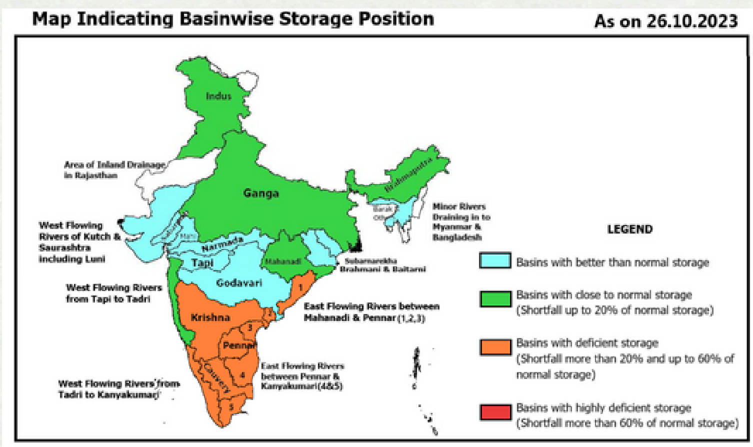

देश में बाढ़ की स्थिति - अक्टूबर 2023

ब्रह्मपुत्र और बराक और झेलम बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2023 को शुरू हुई। 1 मई से 31 अक्टूबर 2023 की अवधि के दौरान, कुल 6269 (4563 स्तर + 1706 प्रवाह) बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए, और 5913 (4334 स्तर + 1579 प्रवाह) पूर्वानुमान 94.32% सटीकता के साथ अनुमेय सीमा के भीतर थे। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से अक्टूबर माह में दो रेड बुलेटिन (अत्यधिक बाढ़ की स्थिति के लिए) एवं 49 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किये गये।

01.05.2023 से 31.10.2023 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

चरम बाढ़ की स्थिति

05 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

क्र.सं.	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1	एनसीटी दिल्ली	उत्तरी दिल्ली	यमुना	दिल्ली रेलवेब्रिज	12/07/2023	15/07/2023
2	उत्तर प्रदेश	बदायूँ	गंगा	कछलाब्रिज	14/07/2023 16/07/2023 29/07/2023 18/08/2023	15/07/2023 22/07/2023 01/08/2023 20/08/2023
3	असम	शिवसागर	दिखो	शिवसागर	17/07/2023 11/08/2023	17/07/2023 12/08/2023
4	तेलंगाना	कुमुराम भीम	वर्धा	सिरपुर नगर	24/07/2023 29/07/2023	24/07/2023 29/07/2023
5	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	तीस्ता	मेल्ली	04/10/2023	04/10/2023

55 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

गंभीर बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड,महाराष्ट्र, राजस्थान, और गुजरात में 76 एफएफ स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली, ओड़िशा, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल और में 65 निगरानी स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, ओडिशा ,मध्य प्रदेश और गुजरात में 44 एफएफ स्टेशन पर बाढ़ की स्थिति सामान्य से ऊपर देखी गई।

सीमा-रेखा से अधिक प्रवाह वाले जलाशय

आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 77 जलाशयों में उनकी सीमा से अधिक प्राप्त हुआ।

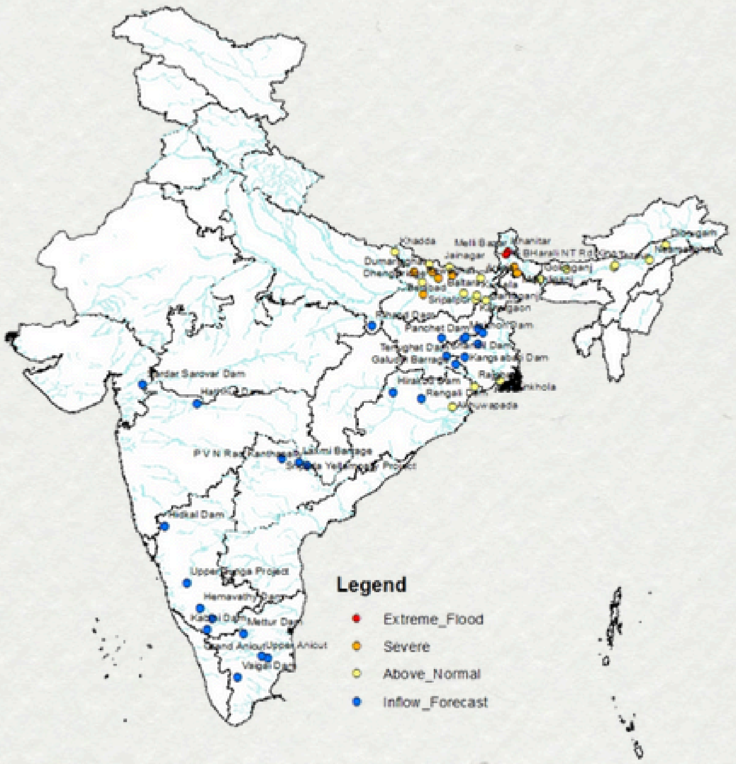

31.10.2023 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्टत: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान (2023-24)	व्यय	व्यय (%में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	162.130	97.1892	59.95%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	20.000	2.6334	3.17%
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	20.310	6.1625	29.63%
4	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	11.000	1.5716	14.29%
5	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	31.58	10.0541	31.83%

राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिज्ञा

के.ज.आ., मुख्यालय, नई दिल्ली

यमुना बेसिन संगठन, नई दिल्ली

सी.एस.आर.ओ., कोइम्ब्तोर

रा.ज. आ., पुणे

नर्मदा बेसिन संगठन, भोपाल

रा.ज. आ., पुणे

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2023 पर सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

के.ज.आ., मुख्यालय, नई दिल्ली

प्रबोधन मध्य संगठन, नागपुर

एम.ई.आर.ओ., भुवनेश्वर

एम.टी.बी.ओ., गांधीनगर।

स्वच्छता ही सेवा "एक तारीख एक घंटा"

क.जी.बी.ओ., हैद्राबाद

एम.ई.आर.ओ., भुवनेश्वर

एम.टी.बी.ओ., गांधीनगर।

नर्मदा बेसिन संगठन, भोपाल

रा.ज.अ., पुणे

टी.एवं बी.डी.बी.ओ., कोलकता

गैलरी

गुजरात सरकार के जल संसाधन संबंधित विभागों के साथ दूसरी त्रैमासिक वार्ता 12.10.2023 को सचिव, डब्ल्यूआरडी, गुजरात की अध्यक्षता में गांधीनगर में आयोजित की गई थी। बैठक सीजीडब्ल्यूबी और सीडब्ल्यूसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी।

संसदीय राजभाषा समिति ने आज धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, शिमला के साथ निरीक्षण बैठक की। इस दौरान समिति ने मंत्रालय एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हो रहे राजभाषा हिंदी के कार्यों का अवलोकन किया।

सीपीडीएसी-उप समिति (सीडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूपीआरएस, एनओआई गोवा, एनसीसीआर और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड-एमएमबी के सदस्य शामिल हैं) की 8वीं बैठक 27.10.2023 को रत्नागिरी, महाराष्ट्र में आयोजित की गई, साथ ही भाटये तट और मिर्या खाड़ी तट पर तटीय सुरक्षा कार्यों का दौरा भी किया गया।

श्री जी.एल.बंसल, मुख्य अभियंता, बीबीओ, सीडब्ल्यूसी, गुवाहाटी ने टीम-नेता के रूप में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए रॉयल सरकार के बीच बाढ़ प्रबंधन पर पुनर्गठित संयुक्त तकनीकी टीम (जेटीटी) की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। भूटान (आरजीओबी) और भारत सरकार की बैठक 5 और 6 अक्टूबर 2023 को फुएंतशोलिंग, भूटान में आयोजित की गई।

इस वर्ष 2023-2024 में हो रहे अंतर मंत्रालयी खेल प्रतियोगिता के तहत हॉकी प्रतियोगिता में जल शक्ति मंत्रालय की टीम ने कांस्य पदक जीता, जिसमे केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल रहे।

सीडब्ल्यूईएस समूह-ए के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 2023 तक प्रसिद्ध पोलावरम परियोजना की पांच दिवसीय परियोजना प्रशंसा यात्रा की।

केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- डॉ. बी.आर.के. पिल्लै, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) – सदस्य
- श्री सुनीलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी–सी)- सदस्य
- श्री श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) – सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in